भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1901
29.11.2019 को उत्तर के लिए

भूमंडलीय तापन का खतरा

1901. श्री मितेष पटेल (बकाभाई) :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भूमंडलीय तापन में हो रही वृद्धि से होने वाले खतरों से निपटने हेतु लोगों के बीच जागरूकता फैलाने हेतु कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) भूमंडलीय तापन में वृद्धि से होने वाली क्षति का आकलन करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(घ) क्या कोई ऐसी योजना/नीति है जिसमें आम नागरिक को भूमंडलीय तापन से निपटने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) सरकार जलवायु परिवर्तन के विषय में जागरूकता सृजित करने और नागरिकों की भागीदारी करने हेतु विभिन्न कदम उठा रही है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

i. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) समाज के सभी वर्गों के बीच पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगों की भागीदारी जुटाने के उद्देश्य से पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय हरित कोर (एनजीसी) कार्यक्रम के तहत लगभग एक लाख स्कूलों को पारिक्लबों के रूप में अभिज्ञात किया गया है, जिनमें लगभग तीस लाख छात्र विभिन्न पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण कार्यकलापों में सक्रियता से भाग ले रहे हैं।
ii. भारत का महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन जागरूकता कार्यक्रम 'साईन्स एक्सप्रैस जलवायु विषयक कार्रवाई विशिष्ट ट्रेन' (एसईसीएएस) था- समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से छात्रों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन विषय पर मोबाइल एक्जीविशन। एसईसीएएस का आशय जलवायु परिवर्तन के विज्ञान; अवलोकित और प्रत्याशित प्रभावों और विभिन्न संभावित प्रतिक्रियाओं के विषय की समझ में वृद्धि करना है। दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 से 7 मई 2016 के दौरान इस ट्रेन ने लगभग 19,800 किमी की दूरी तय की और 23.24 लाख आगंतुकों ने वैश्विक तापन के संबंध में इसकी विषय-वस्तु को देखा। ट्रेन द्वारा अप्रत्याशित प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण, इसे 19,000 किमी की दूरी तय करने के लक्ष्य से 17 फरवरी, 2017 से 8 सितम्बर, 2017 तक दुबारा चलाया गया।
iii. नागरिकों को वहनीय जीवन शैली अपनाने के लिए शामिल करने हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऊर्जा बचाने, जल संरक्षण, वृक्षारोपण पुनर्प्रयोग और पुनर्चक्रण में कमी लाने, जहां संभव हो, वहां कार-पूल अपनाने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने जैसे छोटे-छोटे उपायों को महत्व देने के लिए 'ग्रीन गुड डीड्स' सामाजिक अभियान की शुरूआत की, जिसके द्वारा वैयक्तिक रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में योगदान दिया जा सकता है।

iv. इसके अतिरिक्त, समय-समय पर राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली और मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर और सवाई माधोपुर स्थित इसके चार क्षेत्रीय संग्रहालयों द्वारा आयोजित विभिन्न आऊटरीच कार्यकलापों, थीम पर आधारित प्रदर्शनियों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देने में भी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शामिल रहा है।

v. राष्ट्रीय वहनीय हिमालयी पारिप्रणाली मिशन (एनएमएसएचई) और जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीतिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसकेसीसी) के तहत, 25 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 25 राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठों को सहायता प्रदान की गई है और राज्य प्रकोष्ठों को सुपुर्द किए गए कार्यों में से एक, वैश्विक तापन के खतरे, के विषय में जागरूकता प्रदान करना है। गत पांच वर्षों के दौरान, राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठों द्वारा आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 1.5 लाख लोगों को जानकारी प्रदान की गई है।

vi. भारत, विश्व पर्यावरण दिवस, 2018 का वैश्विक मेजबान देश था। इस आयोजन के दौरान, दिल्ली-एनसीआर के 200 स्कूलों के 10,000 स्कूली छात्रों ने एनवीथॉन -द ग्रीन रन में भाग लिया था।

vii. सरकार, अपने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अनुकूलन उपायों को सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम को भी कार्यान्वित कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हितधारकों और स्थानीय अभिकरणों का क्षमता निर्माण शामिल है।

(ग) जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए भारत सरकार ने ''जलवायु परिवर्तन और भारत: 4x4 आकलन - वर्ष 2030 के लिए सेक्टोरल और क्षेत्रीय विश्लेषण' अध्ययन तैयार किया है। इस अध्ययन में चार प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात् कृषि, जल, प्राकृतिक पारिप्रणाली, जैवविविधता और स्वास्थ्य पर वर्ष 2030 के लिए अवलोकित जलवायु और जलवायु परिवर्तन अनुमानों के संबंध में भारत के चार प्रमुख क्षेत्रों, नामश: हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय संसूचनों के भाग के रूप में मंत्रालय ने भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन कराया है जिसका सारांश 'संवेदनशीलता आकलन और अनुकूलन'' अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने राष्ट्रीय जलवायु रेजिलिएंट कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) परियोजना के तहत कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में अध्ययन भी कराया है।

(घ) और (ड.) वैश्विक तापन के खतरों के विषय में नागरिकों के बीच जागरूकता सृजित करना, भारत की जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के भारत के राष्ट्रीय कार्यढांचे का अभिन्न भाग है जिसमें राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी), राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) और जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (सीसीएपी) शामिल हैं।

****